SHRI AJIT PANJA: The hon. Member's constituency is suffering.

MR. CHAIRMAN; Here she represents the whole State and not a parti cular constituency.

SHRI AJIT PANJA; Actually the area from where she conies. She has brought it to my notice. The area is almost on the border. They are getting most of the programme in Marathi which is creating some difficulty for the people there who speak some other language. I have sent a note to see whether there is any possibility of solving the problem in that area, but I have not yet got the report back.

कृषि-आदानों का स्टाक करने के लिए राज्य-सरकारों को अनुदान

*206. **श्रीमती रत्न कुमारी :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार उर्वरकों तथा अन्य कृषि आदानों का स्टाक करने के लिए राज्य सरकारों को अनुदान देने की किसी योजना पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना को कब तक अन्तिम रूप दे दिये जाने की संभावना है ; और

(ग) क्या इस समय ऐसी कोई योजना विद्यमान है ; यदि हां, तो इसके लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) और (ग) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रीमती रत्न कुमारी : महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि क्या यह सही है कि अभी जो स्कीम सरकार की है, उसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार राज्यों को हर वर्ष बीज, खाद, कीटनाशक अथवा कृषि ऋण आदि के लिए पर्याप्त मात्रा में धन दिया जाता था जिसकी अदायगी राज्य शासन द्वारा 6 महीने के अंदर रियायती ब्याज पर और 9 महीने के अंदर ऊंची ब्याज दरों पर ली जाती थी इससे किसानों को अपनी फसलों के लिए ऋण लेने या कीटनाशक दवाएं लेने में सुविधा मिलती थी। मैं जानना चाहती हूं कि किन कारणों से इस सहायता राशि में कटौती की है और इन राज्यों में मध्य प्रदेश भी शामिल है जिसको उसकी आवश्यकता के अनुरूप यह ऋण सुविधा नहीं दी जा रही है ?

श्री योगेन्द्र मकवाणा : उसमें कोई कटौती नहीं की गई है। पहले यह 200 करोड़ था, अब 260 करोड़ है।

श्रीमती रत्न कुमारी : क्या यह सही है कि वर्ष 1986-87 में इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय शासन से साढ़े 37 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन उसे केवल 11 करोड़ रुपए ही प्राप्त हो सके। तो इस कटौती का क्या कारण है ? क्योंकि यह ऋण शीघ्र ही वापस हो जाता है, अतः भारत सरकार मध्य प्रदेश शासन को उसकी आवश्यकता के अनुरूप धन उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

श्री योगेन्द्र मकवाणा : महोदय, साढ़े 11 करोड़ नहीं 13.44 करोड़ दिया गया है और वह फर्टिल इजर जितना वे कंज्यूम करते हैं उसको लक्ष्य में रखकर दिया जाता है।

श्री अश्विनी कुमार : माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से इस विषय में केवल खाद के बारे में पूछना चाहूंगा कि इस बार देश के बहुत से भागों में वर्षा अत्यंत अल्प हुई है, सब जगह सूखा पड़ा है और पिछले साल दो सालों में इतनी खाद मंगाकर प्रदेशों ने रख ली है और वर्षा के अभाव में उसका प्रयोग नहीं हो पा रहा है और इस प्रकार खाद के मामले में मार्केट में एक ग्लट

आ गया है। किसानों की आवश्यकता आ कम है इसलिए इन सारी बातों को देखते हुए किसानों का प्रोत्साहित करने की दृष्टि से खाद के दामों में विशेष रूप से सरकार कोई सहायता सबसिडी के रूप में राज्यों को देने की सोच रही है जिससे खाद का उपयोग हो सके व फसल अच्छी हो सके ?

SHRI YOGENDRA MAKWANA: This is a suggestion. I will examine it.

SHRl NIRMAL CHATTERJEE: Sir, the fertilizer scene is, as you are aware, very queer. Our public sector units are working much below caacity—less than 50 per cent in some Cases. At the same time imports are on. As a result, a huge stock has been built up. Anybody knows that holding *on* to stocks costs you something. My question is, instead of hearing the cost in that fashion in holding on to stocks and wasting it, why don't you add that subsidy to particularly the poorer sections of agriculturists?

SHRI YOGENDRA MAKWANA: At present, subsidy is given for the transport of the fertilizer upto the block level. This is a new suggestion and as I said earlier, I will examine it.

SHRI PRABHAKAR RAO KALVALA: Sir, Government is providing incentives regarding fertilizers, pesticides etc. to farmers. Water is the main output for agriculture. Are you going to provide any incentives or help to the farmers for constructing open wells or irrigation wells in non-project areas?

SHRI YOGENDRA MAKWANA: This question is about short-term credit to the farmers. This supplementary does not arise from this question.

.MR. CHAIRMAN: Question No. 207.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: It is about irrigation. I cannot reply now.

Shortage of foodgrains

*207. DR. MOHD. HASHIM KIDWAI: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) what is the quantum of foodgrains stored in the godowns of the Food Corporation of India during the year 1986-87 and the current financial year;

(b) the quantum of damages of losses of foodgrains during the period;

(c) the total value of damaged or lost foodgrains during the same period; and

(d) what steps are being taken by Government to minimise these losses or damages?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFALRS AND THE MINISTER OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI H. K. L. BHAGAT): (a) As on 1.4.1986 the total quantity of grains held by different public agencies was 208.59 lakh tonnes. Of this, the stock held by FCI was 149.11 lakh tonnes fin its godowns. The corresponding figure for 1.4.1987 was 195.33 lakh tonnes, of which the stock held by FCI was 147.66 lakh tonnes.

(b) to (d) A statement is laid on the Table of the Sabha as annexure *See.* Appendix CXLIV, Annexure No. 50).

DR. MOHD. HASHIM KIDWAI: Sir, 1 am very thankful to the honourable Minister for stating that some measures have been taken to ensure that there is no loss or damage to the foodgrains. May I know whether the honourable Minister is satisfied that the measures are actually being implemented?

श्री एच० के० एल० भगत : कुछ उपाय किये गये हैं । किसी हद तक फायदा हुआ है। लेकिन मुझे अभी पूरा सन्तोष नहीं है। मैं समझता हूं कि हम